सभी मंडियों में समय-सीमा में हो भुगतान, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

उपज का एक-एक दाना कीमती, भुगतान में देरी बर्दाश्त नहीं : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की किसान हितैषी नीतियों और मंडी बोर्ड की सक्रियता का परिणाम है कि कृषि उपज मंडी समिति चौरई की अपील पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा 64 कृषकों को उनके द्वारा विक्रय की गई उपज की राशि 96 लाख 51 हजार 500 रुपये के भुगतान करने के आदेश प्रसारित हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश में किसान के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृषि उपज मंडी समिति चौरई में पंजीकृत अनुज्ञप्तिधारी फर्म ज्ञाताश्री ट्रेडर्स, चौरई के द्वारा कृषकों से खरीदी गई अधिसूचित कृषि उपज का भुगतान नहीं करने पर मंडी समिति ने त्वरित कार्रवाई की। न्यायालय तहसीलदार, चौरई द्वारा फर्म से वसूली के लिए आर.आर.सी. जारी कर 96,51,500 रुपये (छियानबे लाख इक्यावन हजार पांच सौ रुपये) की वसूली की गई और राशि मंडी समिति के खाते में जमा कराई गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सिविल कोर्ट/जिला कोर्ट से अनुमति नहीं मिलने पर मंडी समिति की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर में अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से ग्रीनको ग्रुप के कार्यकारी निदेशक बंडारू ने की भेंट

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से ग्रीनको ग्रुप के कार्यकारी निदेशक नरसिम्हा राव बंडारू तथा उपाध्यक्ष नवीन कुमार ने समत्व भवन में भेंट कर प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा संबंधी गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। ग्रीनको ग्रुप भारत की अग्रणी नवकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक है। ग्रीनको ग्रुप प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा गतिविधियों के विस्तार का इच्छुक है। यह ग्रुप शिवपुरी जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र और मंदसौर व रतलाम जिलों में पवन ऊर्जा संयंत्र के प्रोजेक्ट संचालित कर रहा है। नीमच जिले में गांधी सागर के पास 1920 मेगावाट क्षमता के भारत के सबसे बड़े पंप हाइड्रो स्टोरेज प्लांट का निर्माण भी 11

हजार करोड़ रूपए के निवेश से किया जा रहा है। इस परियोजना से लगभग 4 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

मंत्री परमार ने विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की

शासन के नियमों के अनुरूप रोस्टर निर्माण करते हुए शीघ्र भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन करें जारी

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने बुधवार को मंत्रालय स्थित सभाकक्ष में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों के साथ, विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की प्रगति सहित विविध विषयों की विस्तृत समीक्षा की। मंत्री परमार ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय, शासन के नियमों के अनुरूप रोस्टर निर्माण करते हुए भर्ती प्रक्रिया के लिए शीघ्र विज्ञापन जारी करें। मंत्री परमार ने कहा कि विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक, अकादमिक एवं प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से, रिक्त पदों की पूर्ति करना हमारी प्राथमिकता है।

मंत्री परमार ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय शैक्षणिक कैलेंडर का दृढ़ता के साथ शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें, इसके लिए पिछले सत्र के परीक्षा परिणाम समयपूर्वक घोषित किए जाएं जिससे अगले सत्र में नियत समय पर प्रवेश, परीक्षा एवं परिणाम सुनिश्चित हो सकें। मंत्री परमार ने कहा कि विद्यार्थियों के समग्र हितों की रक्षा, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री परमार ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया है कि सभी विश्वविद्यालय अपने छात्रावासों को विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुरूप बेहतर बनाएं और छात्रों को सुलभ रूप से गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हो। मंत्री परमार ने विश्वविद्यालयों के छात्रावासों के निरीक्षण के लिए एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए, यह कमेटी छात्रावासों में विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगी। मंत्री परमार ने विश्वविद्यालयों द्वारा डिजिटल मूल्यांकन को लेकर हो रहे क्रियान्वयन की गति को बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि परीक्षा की विश्वसनीयता को प्रभावी रूप से बनाए रखना हमारा ध्येय है और पारदर्शितापूर्ण परीक्षा पद्धति के लिए डिजिटल मूल्यांकन की महती आवश्यकता है। मंत्री परमार ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय डिजिटल मूल्यांकन की पद्धति को लागू करने के लिए प्रयास करें। मंत्री परमार ने कहा कि विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक अमले के कार्यों के मूल्यांकन के लिए भी आंतरिक पद्धति विकसित करे जिससे शैक्षणिक एवं अकादमिक गुणवत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके।

मंत्री परमार ने सभी विश्वविद्यालयों को अन्य भारतीय भाषाओं को क्रेडिट से जोड़कर पढ़ाने की कार्ययोजना को भी शीघ्र लागू करने के प्रयास करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल को तमिल, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर को कन्नड़, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर को मराठी एवं तेलगू, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर को तेलगू एवं पंजाबी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा को सिंधी और गुजराती, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन को मलयालम,सिंधी और असमिया, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर को गुजराती, राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय छिन्दवाड़ा को तमिल और मराठी, पंडित शंम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल को बांग्ला, क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन को गुजराती, महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय चित्रकूट को उड़िया और महर्षि पाणिनी विश्वविद्यालय उज्जैन को उड़िया भाषा सिखाने के लिए भाषा का आवंटन किया गया है। ये विश्वविद्यालय, उक्त आवंटित भाषा सिखाने के लिए क्रियान्वयन कर रहे हैं। मंत्री परमार ने सभी विश्वविद्यालयों को समर्थ पोर्टल पर क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय, स्वयं पोर्टल के विनियमन को अपनाएं और स्वयं पोर्टल पर हर विद्यार्थी को कम से एक कोर्स में पंजीयन कराएं।

बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन ने सभी विश्वविद्यालयों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर अपनी ग्रेडिंग सुधारने के लिए भी निर्देशित किया। राजन ने सभी विश्वविद्यालयों को कर्मचारी कल्याण से जुड़े विविध विषयों को शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित पेंशन प्रकरण एवं अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों का शीघ्र निदान करें।

खाद्य मंत्री ने उपार्जन केन्द्रों का किया औचक निरीक्षण

उपार्जन केंद्रों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं: मंत्री

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मंशा के अनुरूप प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बुधवार को भोपाल से सागर जाते समय अचानक रायसेन जिले के सेहतगंज स्थित उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। मंत्री राजपूत ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए तुलाई, खरीदी एवं अन्य व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मौके पर बारदाने का वजन कराया और भरे बोरे के गेहूं का वजन कराया। निरीक्षण के दौरान मंत्री राजपूत ने उपार्जन केंद्र पर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की तथा ऑटो कनेक्टिविटी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने खरीदी के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने और तुलाई प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता न होने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

मौके पर कार्य में थोड़ी शिथिलता पाए जाने पर खाद्य मंत्री राजपूत ने संबंधित सर्वे कर्मचारियों वसुंधरा गौर और शिवराज लोधी को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मंत्री राजपूत ने किसानों से भी सीधा संवाद किया। रंगपुर के किसान किशन गोपी और कैलाश यादव ने बताया कि उन्हें उपार्जन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है तथा उनकी फसल की तुलाई समय पर हो रही है। किसानों ने उपार्जन केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं को संतोषजनक बताया।

मंत्री राजपूत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और गेहूं उपार्जन एवं तुलाई का कार्य समयबद्ध एवं सुचारू रूप से संपन्न किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। खाद्य मंत्री राजपूत इसके बाद रतनपुर के प्रेम वेयर हाउस पहुंचे। वहां पर शेख आबिद सहित कई किसानों ने बताया कि उन्हें उपार्जन में कोई परेशानी नहीं हो रही है।

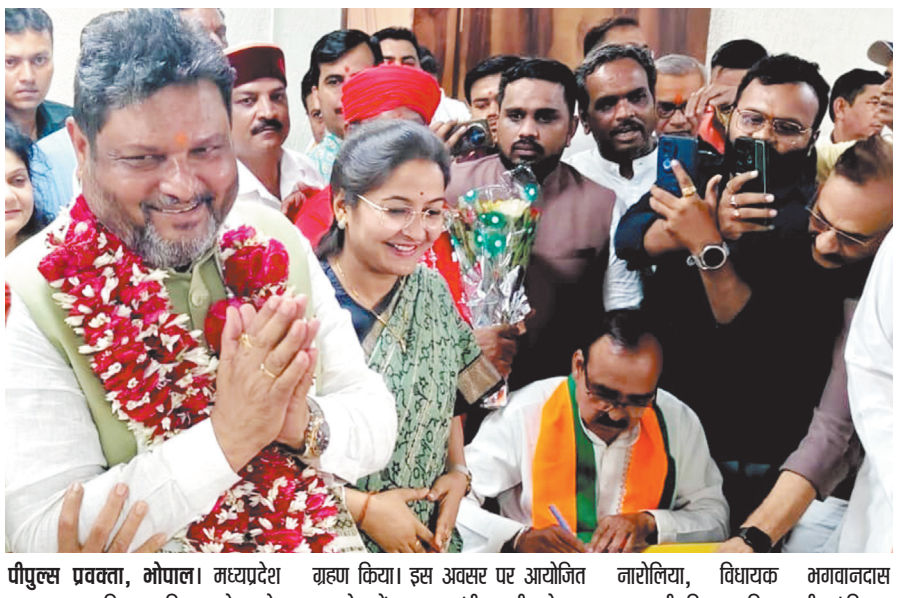

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने ग्रहण किया पदभार

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव तथा सदस्य रामलाल मालवीय एवं बारेलाल अहिरवार ने बुधवार को आयोग में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, सांसद महेंद्र सोलंकी, राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, विधायक भगवानदास सबनानी, विधायक विष्णु खत्री एवं निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

फ्री ट्रेनिंग में रहना-खाना मुफ्त, स्टाइपेंड भी देगी सरकारः राज्यमंत्री गौर

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए निशुल्क ट्रेनिंग देने जा रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए शुरू की गई 'शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना' में उन्हें 45 दिन का निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के 4000 ओबीसी युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का लाभ लेने के लिए 11 मई की शाम 6 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश के ओबीसी वर्ग के युवाओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी संकल्प को साकार करते हुए सैन्य बलों में भर्ती की निःशुल्क कोचिंग के लिए शुरू की गई 'शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना-2026' युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक सौगात है। उन्होंने प्रदेश के ओबीसी वर्ग के प्रतिभावान युवक-युवतियों से इस योजना में बढ़-चढ़कर आवेदन करने की अपील की है। राज्यमंत्री गौर ने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन और निःशुल्क रखी गई है।

4 लाख से अधिक किसानों ने कराया स्लॉट बुक

8.57 लाख किसानों से 48.30 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का हुआ उपार्जन

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि अभी तक 8 लाख 57 हजार किसानों से 48 लाख 30 हजार मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी की जा चुकी है। उन्होंने बताया है की तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक तथा देयक जारी करने का समय रात 12 तक कर दिया गया है। गेहूँ का उपार्जन सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक किया जाता है।

मंत्री राजपूत ने बताया है कि अभी तक 14 लाख 79 हजार किसानों द्वारा गेहूँ उपार्जन के लिए स्लॉट बुक कराए गए हैं। किसानों के हित में गेहूँ उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई 2026 तक की गई। प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर तौल कांटों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 की गई तथा तौल कांटों की संख्या में वृद्धि का अधिकार जिलों को दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही एनआईसी

सर्वर की क्षमता एवं संख्या में वृद्धि कराई गई। खाद्य विभाग द्वारा प्रति घंटा स्लॉट बुकिंग एवं उपार्जन की मॉनिटरिंग की जा रही है। मंत्री राजपूत ने बताया कि किसानों को 8879.42 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उपार्जन केन्द्र पर किसानों की सुविधा के लिए पीने का पानी, बैठने के लिए छायादार स्थान, जन सुविधाए आदि की व्यवस्थाएँ की गई हैं। किसानों के उपज की तौल समय पर हो सके, इस हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं। इसमें बारदाने, तौल कांटे, हम्माल तुलावटी, सिलाई मशीन, कम्प्यूटर, नेट कनेक्शन, गुणवत्ता परीक्षण उपकरण, उपज की साफ सफाई के लिए पंखा, छन्ना आदि की व्यवस्था की गई है। उपार्जन केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं के फोटो ग्राफ्स भारत सरकार के PCSAP पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही की जा रही है।

किसानों से 2585 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस राशि सहित 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ का उपार्जन किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये आवश्यक बारदानों की व्यवस्था की जा चुकी है। उपार्जित गेहूँ की भर्ती जूट बारदाने के साथ साथ [illegible] बेग एवं जूट के एक भर्ती बारदाने का उपयोग किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था की गई, जिससे उपार्जित गेहूँ का सुरक्षित भण्डारण किया जा सके।

लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए प्रदेश में 9 को नेशनल लोक अदालत

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 9 मई शनिवार को प्रदेश के समस्त जिला न्यायालय एवं तहसील के व्यवहार न्यायालयों में 'नेशनल लोक अदालत' का वृहद स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। नागरिकों के कल्याण और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। नेशनल लोक अदालत में नागरिकों को विशेष सुविधा प्रदान करते हुए संपत्ति कर, जल कर एवं अन्य उपभोक्ता कर के लंबित प्रकरणों में देय अधिभार (सरचार्ज) पर 100 प्रतिशत तक की अभूतपूर्व छूट प्रदान की जा रही है। योजना के प्रावधानों के अंतर्गत 50 हजार रुपये तक के संपत्ति कर और 10 हजार रुपये तक के जल कर की बकाया राशि वाले प्रकरणों में सरचार्ज पूर्णतः माफ किया जाएगा। इससे अधिक की बकाया राशि होने पर निर्धारित स्लैब के अनुरूप सरचार्ज में 25 से 75 प्रतिशत तक की रियायत का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की बकाया राशि पर यह विशेष छूट वन टाइम सेटलमेंट के रूप में देय होगी।

कमजोरियों से नेतृत्व तकः युवा चेंज मेकर्स का एक प्रेरक संगम

आपको अपने अधिकारों के लिए हमेशा आवाज उठानी ही चाहिए

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

'अपनी ऊर्जा और जोश को हमेशा बनाए रखें। हम आपकी बात सुनने के लिए यहां मौजूद हैं।' भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने सम्बोधित करते हुए कही। 'आपको अपने अधिकारों के लिए हमेशा आवाज उठानी ही चाहिए। पुलिस हमेशा आपके साथ है।'

मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सामुदायिक सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे कुछ अभियानों को साझा करते हुए, मंजुलता खत्री (अतिरिक्त डीसीपी महिला अपराध, एजेके) ने सभी किशोरों और महिलाओं से यह बात कही। उपरोक्त विचार अतिथियों द्वारा आर.के.डी.एफ. मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, भोपाल में आयोजित 'सृजन सम्मेलन' कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए गए। कार्यक्रम का

संयुक्त आयोजन मध्यप्रदेश पुलिस, भोपाल पुलिस कमिश्नरेट, आर.के.डी.एफ. एवं उदय सामाजिक विकास संस्था द्वारा किया गया। वर्ष 2022 से मध्यप्रदेश पुलिस के कम्युनिटी पुलिस विंग के माध्यम से संचालित 'सृजन किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम' का उद्देश्य वंचित किशोर-किशोरियों, विशेष रूप से बालिकाओं, को न्याय तक पहुँच और सशक्तिकरण के अवसर उपलब्ध कराना है। यह पहल विभिन्न विभागों एवं उदय संस्था जैसे सिविल सोसायटी संगठनों के सहयोग व समन्वय से संचालित की जा रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत किशोरों को आत्मरक्षा, एथलेटिक्स, संवैधानिक मूल्यों, करियर मार्गदर्शन एवं जीवन कौशल से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किये जाते हैं। डॉ. लिजी थॉमस, उदय संस्था निर्देशिका, ने साझा किया की वर्तमान में मध्यप्रदेश के 35 जिलों में 7,000 से अधिक सृजन किशोर-किशोरियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से सशक्त किया जा चुका है।

कार्यक्रम में 250 से अधिक किशोर-किशोरियों, महिलाओं एवं पुरुषों ने भाग लिया। इस दौरान सृजन किशोरों द्वारा अपनी प्रेरणादायक सफलता की कहानियों तथा मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण का प्रदर्शन भी किया गया। इनके बाद किशोरों और महिलाओं ने समुदाय में अपने चेलेंजेज़ पर अपने विचार एक जन संवाद कार्यक्रम में साझा किये7 उदय संस्था टीम द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस की कम्युनिटी पुलिसिंग पहलों में अपने योगदान को भी एक ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। अंत में, आर.के.डी.एफ. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और करियर परामर्श पर संक्षिप्त सत्र भी आयोजित किये गए।

इस अवसर पर उपस्थित अन्य विशिष्ट व्यक्तियों में आरकेडीएफ समूह की चांसलर डॉ. साधना कपूर और रजनीश कश्यप कौल (एसीपी मिसरोद जोन II) शामिल थे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ एक सशक्त और लैंगिक-समान भविष्य के निर्माण का सामूहिक संकल्प लिया गया।